OVERVIEW

It is, therefore, appropriate that we begin the story with a discussion of the Cold War. The chapter shows how the dominance of two superpowers, the United States of America and the Soviet Union, was central to the Cold War. It tracks the various arenas of the Cold War in different parts of the world. The chapter views the Non Aligned Movement (NAM) as a challenge to the dominance of the two superpowers and describes the attempts by the non-aligned countries to establish a New International Economic Order (NIEO) as a means of attaining economic development and political independence. It concludes with an assessment of India's role in NAM and asks how successful the policy of nonalignment has been in protecting India's interests.

परिचय

इस अध्याय से यह साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीतयुद्ध के केंद्र में था। यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीतयुद्ध की समरस्थलियों तक भी ले जाएगा। इस अध्याय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से विचार किया गया है कि किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा 'नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था' स्थापित करने के प्रयास की चर्चा इस अध्याय में यह बताते हुए की गई है कि किस तरह इन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। अध्याय के अंत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है और यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा में गुटनिरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही।

The Truman Doctrine, 1947

With the Truman Doctrine, President Harry S. Truman established that the United State would provide political, military & economic assistance to all democratic nations under threat from external or internal authoritarian forces. The Truman Doctrine effectively reoriented U.S. foreign policy, away from its usual stance of withdrawal from regional conflicts not directly involving the United

States, to one of possible intervention in

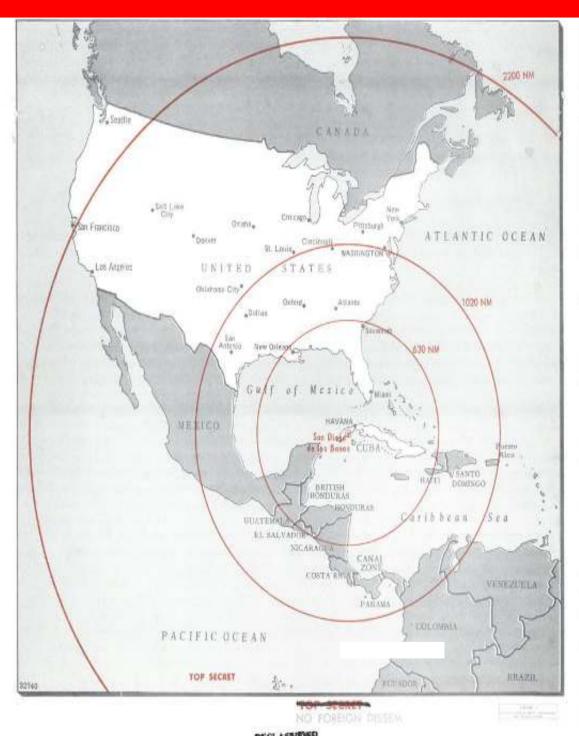
Marshaff Plan, formally European Recovery Program, (April 1948 – Dec.1951), U.S. – sponsored program designed to rehabilitate the economies of 17 western & southern European countries in order to create stable conditions in which democratic institutions could survive.

ट्रमैन सिद्धांत, 1947

दूमैन सिद्धांत के साथ, राष्ट्रपति हैरी एस। दूमैन ने स्थापित किया कि संयुक्त राज्य बाहरी या आंतरिक सत्तावादी बलों से खतरे के तहत सभी लोकतांत्रिक देशों को राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। दूमैन सिद्धांत ने अमेरिकी विदेश नीति को प्रभावी रूप से फिर से संगठित किया, क्षेत्रीय संघर्षों से वापसी के अपने सामान्य रुख से दूर, संयुक्त राज्य अमेरिका को सीधे शामिल नहीं करना, दूर के संघर्षों में संभावित हस्तक्षेप में से एक को।

मार्शल प्लान, औपचारिक रूप से यूरोपीय रिकवरी प्रोग्राम, (अप्रैल 1948 - Dec. 1951), यू.एस. - प्रायोजित कार्यक्रम जिसमें 17 पश्चिमी और दक्षिणी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्वास के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि स्थिर स्थिति बनाई जा सके जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाएं जीवित रह सकें।

Map showing the range of the nuclear missiles under construction in Cuba, used during the secret meetings on the Cuban missile crisis



यह नक्शा क्यूबा में तैनात की जा रही परमाणु मिसाइल की पहुँच का दायरा दिखाता है। नक्शे के नीचे ध्यान से देखिए। यह नक्शा संयुक्त राष्ट अमरीका की खुफिया एजेंसी सी.आई.ए. द्वारा क्यूबा मिसाइल संकट पर हुई गोपनीय बैठक में प्रयोग किया गया था।

CUBAN MISSILE CRISIS

In April 1961, the leaders of the **Union of Soviet Socialist** Republics (USSR) were worried that the United States of America (USA) would invade communist-ruled Cuba and overthrow Fidel Castro, the president of the small island nation off the coast of the United States. Cuba was an ally of the Soviet Union and received both diplomatic and financial aid from it. Nikita Khrushchev, the leader of the **Soviet Union, decided to** convert Cuba into a Russian base

क्यूबा का मिसाइल संकट

1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमरीका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्तापलट हो जाएगा। क्यूबा अमरीका के तट से लगा हुआ एक छोटा-सा द्वोपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनियक तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता नीकिता खु श्चेव ने क्यूबा को रूस के 'सैनिक अड्डे' के रूप में बदलने का फैसला किया।

In 1962, he placed nuclear missiles in Cuba. The installation of these weapons put the US, for the first time, under fire from close range and nearly doubled the number of bases or cities in the American mainland which could be threatened by the USSR.

1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दीं। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमरीका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमरीका के मुख्य भू-भाग के लगभग दोगुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था।

Three weeks after the **Soviet Union had placed** the nuclear weapons in **Cuba, the Americans** became aware of it. The **US President, John F.** Kennedy, and his advisers were reluctant to do anything that might lead to full-scale nuclear war between the two countries, but they were determined to get Khrushchev to remove the missiles and nuclear weapons from Cuba.

क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमरीकियों को तीन हफ्ते बाद लगी। अमरीकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार एसा कुछ भी करने से हिचिकचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाण् युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ थे कि खुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा लें। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमरीकी जंगी बेडों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए।

Kennedy ordered American warships to intercept any Soviet ships heading to Cuba as a way of warning the USSR of his seriousness. A clash seemed imminent in what came to be known as the **Cuban Missile Crisis. The** prospects of this

कैनेडी ने आदेश दिया कि अमरीकी जंगी बेडों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। इस तरह अमरीका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। एसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को 'क्यूबा मिसाइल संकट' के रूप में जाना गया। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। यह टकराव

The prospects of this clash made the whole world nervous, for it would have been no ordinary war. Eventually, to the world's great relief, both sides decided to avoid war. The Soviet ships slowed down and turned back.

यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता। अंतत: दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की साँस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धोमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया।

The Cuban Missile Crisis was a high point of what came to be known as the Cold War. The **Cold War referred to the** competition, the tensions and a series of confrontations between the United States and Soviet Union, backed by their respective allies. Fortunately, however, it never escalated into a 'hot war', that is, a fullscale war between these two powers. There were wars in various regions, with the two powers and their allies involved in warfare and in supporting regional allies, but at least the world avoided another global war

'क्यूबा मिसाइल संकट' शीतयुद्ध का चरम बिंदु था। शीतयुद्ध सोवियत संघ और अमरीका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता. तनाव और संघर्ष की एक गुंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया यानी इन दो देशों के बीच कोई पूर्णव्यापी रक्तरंजित युद्ध नहीं छिडा। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए; दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे; वे क्षेत्र-विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने लेकिन दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध से बच गई।

The Cold War was not simply a matter of power rivalries, of military alliances, and of the balance of power. These were accompanied by a real ideological conflict as well, a difference over the best and the most appropriate way of organising political, economic, and social life all over the world. The western alliance, headed by the US, represented the ideology of liberal democracy and capitalism while the eastern alliance, headed by the Soviet Union, was committed to the ideology of socialism and communism.

शीतयुद्ध सिर्फ जोर-आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति-संतुलन का मामला भर नहीं था बल्कि इसके साथ-साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन-सा है। पश्चिमी गठबंधन का अगुआ अमरीका था और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूँजीवाद का समर्थक था। पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी।

WHAT IS THE COLD WAR?

The end of the Second World War is a landmark in contemporary world politics. In 1945, the Allied Forces, led by the US, Soviet Union, Britain and France defeated the Axis Powers led by Germany, Italy and Japan, ending the Second World War (1939- 1945).

शीतयुद्ध क्या है?

दूसरे विश्वयुद्ध का अंत समकालीन विश्व-राजनीति का एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है। सन् 1945 में मित्र-राष्ट्रों और धरी-राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध (1939-1945) की समाप्ति हो गई।

The war had involved almost all the major powers of the world and spread out to regions outside Europe including Southeast Asia, China, Burma (now Myanmar) and parts of India's northeast. The war devastated the world in terms of loss of human lives and civilian property. The First World War had earlier shaken the world between 1914 and 1918.

मित्र-राष्ट्रों की अगुआई अमरीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। धरी-राष्ट्रों की अगुआई जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में थी। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। यह युद्ध यरोप से बाहर के इलाके में भी फैला और इसका विस्तार दक्षिण-पूर्व एशिया, चीन, बर्मा (अब म्यांमार) तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धनहानि हुई। 1914 से 1918 के बीच हुए पहले विश्वयुद्ध ने विश्व को दहला दिया था, लेकिन दूसरा विश्वयुद्ध इससे भी ज्यादा भारी पडा।

The end of the Second World War was also the beginning of the Cold War. The world war ended when the United States dropped two atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, causing Japan to surrender. Critics of the US decision to drop the bombs have argued that the US knew that Japan was about to surrender and that it was unnecessary to drop the bombs.

दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति से ही शीतयुद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में अमरीका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराये और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्वयुद्ध का अंत हुआ। परमाणु बम गिराने के अमरीकी फैसले के आलोचकों का तर्क है कि अमरीका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। एसे में बम गिराना गैर-ज़रूरी था

They suggest that the US action was intended to stop the Soviet Union from making military and political gains in Asia and elsewhere and to show Moscow that the United States was supreme. US supporters have argued that the dropping of the atomic bombs was necessary to end the war quickly and to stop further loss of American and Allied lives.

इन आलोचकों का मानना है कि अमरीका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमरीका ही सबसे बडी ताकत है। अमरीका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमरीका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जुरूरी था।

Whatever the motives, the consequence of the end of the Second World War was the rise of two new powers on the global stage. With the defeat of Germany and Japan, the devastation of **Europe and in many other** parts of the world, the **United States and the Soviet Union became the** greatest powers in the world with the ability to influence events anywhere on earth.

विश्वयुद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हों, लेकिन इसका परिणाम यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हो गया। जर्मनी और जापान हार चुके थे और यरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झल रहे थे। अब अमरीका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बडी शक्ति थे। इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सकें।

While the Cold War was an outcome of the emergence of the US and the USSR as two superpowers rival to each other, it was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bombs is too costly for any country to bear. The logic is simple yet powerful. When two rival powers are in possession of nuclear weapons capable of inflicting death and destruction unacceptable

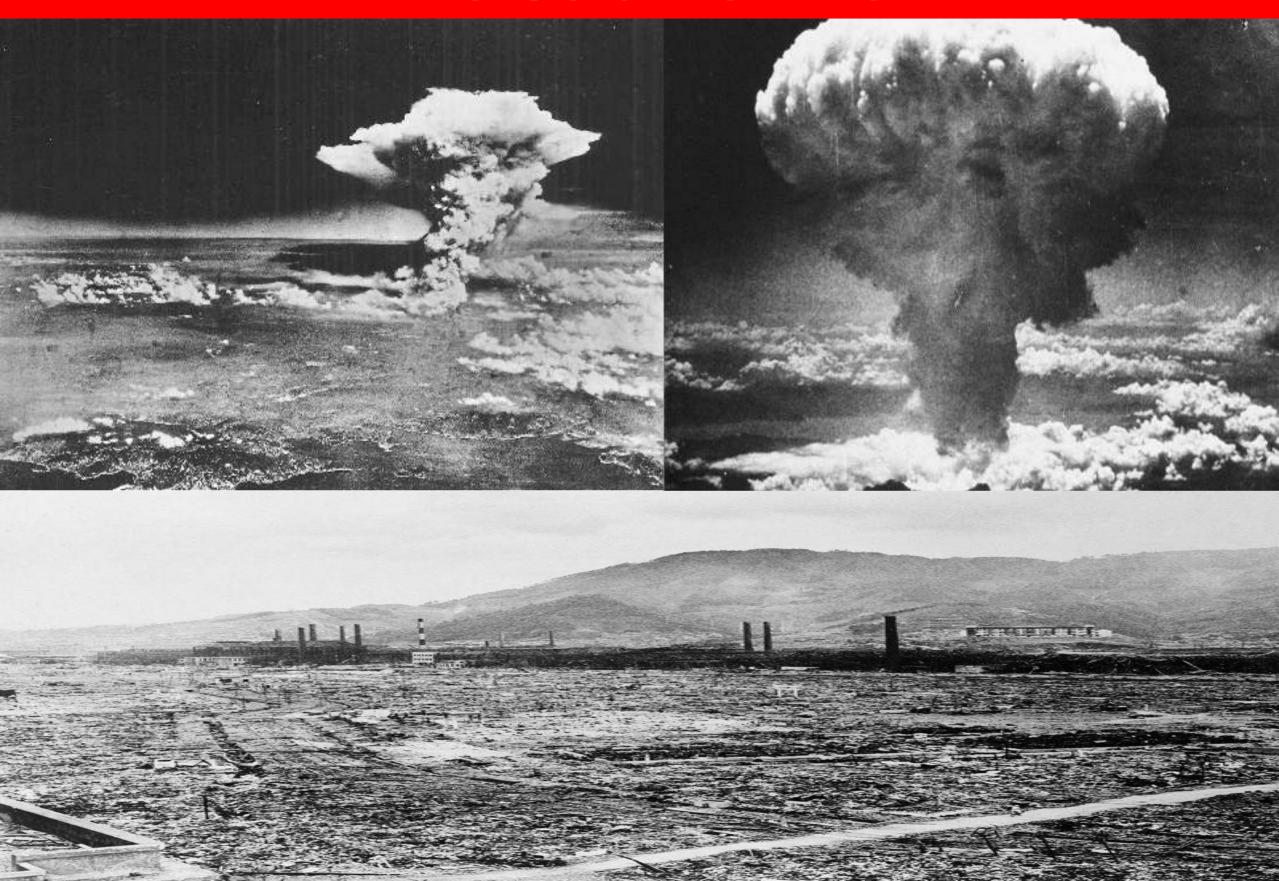
अमरीका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड में एक-दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीतयुद्ध का कारण बना। शीतयुद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झलना किसी भी राष्ट के बूते की बात नहीं। यह एक सीधा-सादा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हों कि वे एक-दूसरे को असहनीय क्षति पहुँचा सकें तो एसे में दोनों के बीच रक्तरंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है।

a full-fledged war is unlikely. In spite of provocations, neither side would want to risk war since no political gains would justify the destruction of their societies.

उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम मोल लेना नहीं चाहेगा क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता।

In the event of a nuclear war, both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declar e one side or the other as the winner. Even if one of them उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की tries to attack and disable the nuclear weapons of its rival, the other would still be left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction. This is called the logic of 'deterrence': both sides have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can affor d to initiate war. Thus, the Cold War — in spite of being an intense form of rivalry between great powers remained a 'cold' and not hot or shooting war. The deterrence relationship provents war but not

परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है - यह तय करना भी असंभव होगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके कोशिश करता है तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे 'अपरोध' (रोक और संतुलन) का तर्क कहा गया। दोनों ही पक्षों के पास एक-दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुँचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। इस तरह, महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वन्द्विता होने के बावजूद शीतयुद्ध रक्तरंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। इसकी तासीर ठंडी रही। पारस्परिक 'अपरोध' की स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता को न रोक सकी।





These pictures depict the destruction caused by the bombs dropped by the US on Hiroshima (the bomb was codenamed 'Little Boy') and Nagasaki (code-named 'Fat Man'). Yet, these bombs were very small in their destructive capacity (measured in terms of kiloton yield) as compared to the nuclear bombs that were to be available in the stockpiles assembled by the superpowers. The yield of Little Boy and Fat Man were 15 and 21 kilotons respectively. By the early 1950s the US and the USSR were already making thermonuclear weapons that had a yield between 10 and 15 thousand kilotons. In other words, these bombs were a thousand times more destructive than the bombs used in Hiroshima and Nagasaki. During much of the Cold War, both the superpowers possessed thousands of such waanane .lust imaaina tha aytant af



ये तस्वीरें उस विध्वंस को दिखाती हैं जो अमरीका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराये गये परमाणु बमों के कारण हुआ। इन बमों को 'लिटिल ब्वॉय' और 'फैटमैन' के गुप्तनाम दिए गए। महाशक्तियों के पास आज परमाणु हथियारों का जो ज़खीरा है उसकी तुलना में ये बम बहुत छोटे थे। ये बम क्रमश: 15 और 21 किलोटन क्षमता के थे। इतनी कम क्षमता के परमाणु बमों ने भी अकल्पनीय विध्वंस किया। 1950 के दशक की श्रुआत में ही संयुक्त राष्ट अमरीका और सोवियत संघ एसे परमाणु-बमों का परीक्षण कर रहे थे जिनकी क्षमता 10 से 15 हजार किलोटन थी। दूसरे शब्दों में ये बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराये गये परमाणु बमों की तुलना में हजारों गुना ज्यादा विध्वंसक थे। शीतयुद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों के पास इस तरह के हजारों हथियार थे। जरा कल्पना कीजिए कि ये हथियार दुनिया भर में क्या तबाही मचा सकते थे।



Map showing the way Europe was divided into rival alliances during the Cold War

THE EMERGENCE OF TWO POWER

BLOCS The two superpowers were keen on expanding their spheres of influence in different parts of the world. In a world sharply divided between the two alliance systems, a state was supposed to remain tied to its protective superpower to limit the influence of the other superpower and its allies.

दो-ध्वीय विश्व का आरंभ

दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थीं। दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बँट गई थी। एसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके।

The smaller states in the alliances used the link to the superpowers for their own purposes. They got the promise of protection, weapons, and economic aid against their local rivals, mostly regional neighbours with whom they had rivalries. The alliance systems led by the two superpowers, therefore, threatened to divide the entire world into two camps. This division happened first in Europe. **Most countries of western Europe sided with the US and** those of eastern Europe joined the Soviet camp. That is why these were also called the

परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने-अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंद्वी देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला. हथियार और आर्थिक मदद मिली। इन देशों की अपने पड़ोसी देशों से होड थी। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया के दो खेमों में बंट जाने का खतरा पैदा हो गया। यह विभाजन सबसे पहले य्रोप में हुआ। पश्चिमी यरोप के अधिकतर देशों ने अमरीका का पक्ष लिया जबकि पूर्वी य्रोप सोवियत खेमे में शामिल हो गया इसीलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं।

The western alliance was formalised into an organisation, the North **Atlantic Treaty Organisation** (NATO), which came into existence in April 1949. It was an association of twelve states which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them. Each of these states would be obliged to help the other. The eastern alliance, known as the Warsaw Pact, was led by the Soviet Union. It was created in 1955 and its principal function was to

पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की स्थापना हुई जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमरीका अथवा यरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे 'संगठन' में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। 'नाटो' में शामिल हर देश एक-दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को 'वारसा संधि' के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुआई सोवियत संघ ने की। इसकी स्थापना सन् 1955 में हुई थी और इसका मुख्य काम था 'नाटो' में शामिल देशों का यरोप में मुकाबला करना।

International alliances during the **Cold War era were determined by** the requirements of the superpowers and the calculations of the smaller states. As noted above, Europe became the main arena of conflict between the superpowers. In some cases, the superpowers used their military power to bring countries into theirrespective alliances. Soviet intervention in east Europe provides an example. The Soviet Union used its influence in eastern Europe, backed by the very large presence of its armies in the countries of the region, to ensure that the eastern half of **Europe remained within its**

शीतयुद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की ज़रूरतों और छोटे देशों के लाभ-हानि के गणित से होता था। जैसाकि ऊपर बताया गया है, महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा य्रोप बना। कुछेक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने-अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। पूर्वी य्रोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका उदाहरण है। सोवियत संघ ने पूर्वी य्रोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि य्रोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे।

In East and Southeast Asia and in West Asia (Middle East), the United States built an alliance system called - the **Southeast Asian Treaty Organisation (SEATO) and** the Central Treaty **Organisation (CENTO).** The Soviet Union and communist China responded by having close relations with regional countries such as North Vietnam, North Korea and Iraq.

पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमरीका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिण-पूर्व एशियाई संधि संगठन (SEATO) और केंद्रीय संधि संगठन (CENTO) कहा जाता है। इसके ज़वाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने सम्बन्ध मजबूत किए।

The Cold War threatened to divide the world into two alliances. Under these circumstances, many of the newly independent countries, after gaining their independence from the colonial powers such as Britain and France, were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence. **Cracks and splits within the** alliances were quick to appear. **Communist China quarrelled** with the USSR towards the late 1950s, and, in 1969, they fought a brief war over a territorial dispute. The other important development was the Non-Aligned Movement (NAM), which dave the newly independent

शीतयुद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बँट जाने का खतरा पैदा हो गया था। एसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन, मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को चिंता हुई कि कहीं वे अपनी इस आज़ादी को पाने के साथ खो न बैठें। गठबंधन में भेद पैदा हुए और बड़ी जल्दी उनमें दरार पड़ी। साम्यवादी चीन की 1950 के दशक के उत्तरार्द्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई। सन् 1969 में इन दोनों के बीच एक भू-भाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा-सा युद्ध भी हुआ। इस दौर की एक महत्त्वपूर्ण घटना 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन' का विकास है। इस आंदोलन ने नव-स्वतंत्र राष्ट्रों को दो-ध्वीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया।

You may ask why the superpowers needed any allies at all. After all, with their nuclear weapons and regular armies, they were so powerful that the combined power of most of the smaller states in Asia and Africa, and even in Europe, was no match to that of the superpowers. Yet, the smaller states were helpful for the superpowers in gaining access to

आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आख़िर अपने परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना के बूते महाशक्तियां इतनी ताकतवर थीं कि एशिया तथा अफ्रीका और यहां तक कि य्रोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन, हमें यह समझने की ज़रूरत है कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे -

- (i) vital resources, such as (क) महत्त्वपूर्ण संसाधनों (जैसे तेल oil and minerals, और खनिज),
- (ii) territory, from where the superpowers could launch their weapons and troops,
- (iii)locations from where they could spy on each other, and
- (iv)economic support, in that many small allies together could help pay for military expenses.

- (ख) भू-क्षेत्र (तािक यहां से महाशिक्तयां अपने हिथयारों और सेना का संचालन कर सकें),
- (ग) सैनिक ठिकाने (जहां से महाशक्तियां एक-दूसरे की जासूसी कर सकें) और
- (घ) आर्थिक मदद (जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे-छोटे देश सैन्य-खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे)।

They were also important for ideological reasons. The loyalty of allies suggested that the superpowers were winning the war of ideas as well, that liberal democracy and capitalism were better than socialism and communism, or vice versa.

ये एसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए ज़रूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण भी ये देश महत्त्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही हैं। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थीं कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है अथवा समाजवाद और साम्यवाद. उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है।

ARENAS OF THE COLD WAR शीतयुद्ध के दायरे

Sometimes, countries outside the two blocs, for example, the non-aligned countries, played a role in reducing Cold War conflicts and averting some grave crises. Jawaharlal Nehru — one of the key leaders of the NAM — played a crucial role in mediating between the two Koreas.

एसे कई मौके आए जब शीतयुद्ध के संघषों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभायी। इस संदर्भ में गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

In the Congo crisis, the **UN Secretary-General** played a key mediatory role. By and large, it was the realisation on a superpower's part that war by all means should be avoided that made them exercise restraint and behave more responsibly in international affairs. As the Cold War rolled from one arena to another, the logic of restraint was increasingly evident.

कांगो संकट में संयुक्त राष्ट संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अंतत: यह बात उभरकर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हालत में टालना ज़रूरी है। इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी भरा बरताव किया। शीतयुद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया और इसमें संयम का तर्क ही काम कर रहा था।

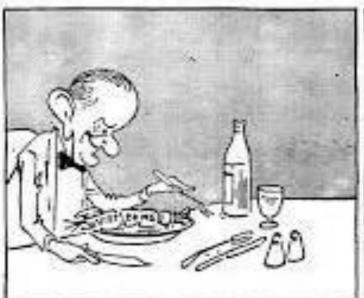
However, since the Cold War did not eliminate rivalries between the two alliances, mutual suspicions led them to arm themselves to the teeth and to constantly prepare for war. Huge stocks of arms were considered necessary to prevent wars from taking place.

हालाँकि शीतयुद्ध के दौरान दोनों ही
गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंदिता समाप्त
नहीं हुई थी। इसी कारण एक-दूसरे
के प्रति शंका की हालत में दोनों गुटों
ने भरपूर हथियार जमा किए और
लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे।
हथियारों के बड़े ज़खीरे को युद्ध से
बचे रहने के लिए ज़रूरी माना गया।

Drawn by wellknown **Indian cartoonist** Kutty, these two cartoons depict an Indian view of the Cold War. The first cartoon was drawn when the US entered into a secret understanding with China, keeping the USSR in the dark. Find out more about the characters in the cartoon. The second cartoon depicts the **American** misadventure in Vietnam. Find out more about the Vietnam War.

Drawn by wellknown Indian cartoonist Kutty. these two cartoons depict an Indian view of the Cold War. The first cartoon was drawn when the US entered Into a secret understandina with China, keeping the USSR in the dark. Find out more about the characters in the cartoon. The second cartoon depicts the American misadventure In Vietnam, Find out more about the Vietnam







कार्टूनिस्ट कु'ी ने बनाए हैं। इनमें

FOOD FOR THOUGHT President Jhonson is in more troubles over Vietnam.

In time, therefore, the US and USSR decided to collaborate in limiting or eliminating certain kinds of nuclear and nonnuclear weapons. A stable balance of weapons, they decided, could be maintained through 'arms control'. Starting in the 1960s, the two sides signed three significant agreements within a decade.

इस कारण. समय रहते अमरीका और सोवियत संघ ने कुछेक परमाण्विक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि 'अस्त्र-नियंत्रण' द्वारा हथियारों की होड पर लगाम कसी जा सकती है और उसमें स्थायी संतुलन लाया जा सकता है। एसे प्रयास की शुरुआत सन् 1960 के दशक के उत्तरार्द्ध में हुई और एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने तीन अहम समझौतों पर दस्तख़त किए।

These were the Limited **Test Ban Treaty, Nuclear NonProliferation Treaty** and the Anti-Ballistic Missile Treaty. Thereafter, the superpowers held several rounds of arms limitation talks and signed several more treaties to limit their arms.

ये संधियाँ थीं परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि (एंटी बैलेस्टिक मिसाइल ट्रीटी)। इसके बाद महाशिक्तयों ने 'अस्त्र-परिसीमन' के लिए वार्ताओं के कई दौर किए और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियाँ कीं।

CHALLENGE TO BIPOLARITY

We have already seen how the Cold War tended to divide the world into two rival alliances. It was in this context that nonalignment offered the newly decolonised countries of Asia, Africa and Latin America a third option—not to join either alliance.

दो-ध्वीयता को चुनौती - गुटनिरपेक्षता

हम देख चुके हैं कि किस तरह शीतयुद्ध की वज़ह से विश्व दो प्रतिद्वंद्वी गुटों में बँट रहा था। इसी संदर्भ में गुटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमरीका के नव-स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का।

The roots of NAM went back to the friendship between three leaders — Yugoslavia's Josip Broz Tito, India's Jawaharlal Nehru, and **Egypt's leader Gamal Abdel** Nasser — who held a meeting in 1956. Indonesia's **Sukarno and Ghana's Kwame Nkrumah strongly** supported them. These five leaders came to be known as the five founders of NAM. The first non-aligned summit was held in Belgrade in 1961. This was the culmination of at least three

गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड में यगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज़ टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीनों ने सन् 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकणों और घाना के वामे एनक्रमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये पाँच नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन केसंस्थापक कहलाए। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन् 1961 में बेलग्रेड में हुआ। यह सम्मेलन कम से कम तीन बातों की परिणति था -

- (i) cooperation among these five countries,
- (ii) growing Cold War tensions and its widening arenas, and
- (iii)the dramatic entry of many newly decolonised African countries into the inter national arena

The first summit was attended by 25 member states. Over the years, the membership of NAM has expanded.

- (क) इन पाँच देशों के बीच सहयोग,
- (ख) शीतयुद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, और
- (ग) अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव-स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय।

पहले गुटनिनरपेक्ष-सम्मेलन में 25 सदस्य- देश शामिल हुए। समय गुजरने के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई।

As non-alignment grew into a popular international movement, countries of various different political systems and interests joined it. This made the movement less homogeneous and also made it more difficult to define in very neat and precise terms: what did it really stand for? Increasingly, NAM was easier to define in terms of what it was not. It was not about being a member of an alliance.

जैसे-जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया वैसे-वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग-अलग हितों के देश शामिल होते गए। इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। इसी कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना कुछ मुश्किल है। वास्तव में यह आंदोलन है क्या? दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है- यह बताकर इसकी परिभाषा करना ज्यादा सरल है। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है।

The policy of staying away from alliances should not be considered isolationism or neutrality. Non-alignment is not isolationism since isolationism means remaining aloof from world affairs. Isolationism sums up the foreign policy of the US from the **American War of** Independence in 1787 up to the beginning of the First World War.

महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं है कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग-थलग रखते हैं या तटस्थता का पालन करते हैं। गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं। पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काटकर रखना। 1787 में अमरीका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। इसके बाद से पहले विश्वयुद्ध की शुरुआत तक अमरीका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा।

In comparison, the nonaligned countries, including India, played an active role in mediating between the two rival alliances in the cause of peace and stability. Their strength was based on their unity and their resolve to remain nonaligned despite the attempt by the two superpowers to bring them into their alliances.

उसने पृथकतावाद की विदेश-नीति अपनाई थी। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने-अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद एसे किसी खेमे में शामिल न होने के उनके संकल्प में है।

Non-alignment is also not neutrality. Neutrality refers principally to a policy of staying out of war. States practising neutrality are not required to help end a war. They do not get involved in wars and do not take any position on the appropriateness or morality of a war. Non-aligned states, including India, were actually involved in wars for various reasons. They also worked to prevent war between others and tried to end wars that had broken out.

गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यत: युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह ज़रूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। एसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही -ग़लत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया है और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किए हैं।

NEW INTERNATIONAL ECONOMIC ORDER

The non-aligned countries were more than merely mediators during the Cold War. The challenge for most of the non-aligned countries — a majority of them were categorised as the Least Developed Countries (LDCs) — was to थी। be more developed economically and to lift their people out of poverty.

नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था

गुटनिरपेक्ष देश शीतयुद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांशेशों को 'अल्प विकसित देश' का दर्जा मिला था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की

Economic development was also vital for the independence of the new countries. Without sustained development, a country could not be truly free. It would remain dependent on the richer countries including the colonial powers from which political freedom had been achieved.

नव-स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्त्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायनों में आज़ाद नहीं रह सकता। उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता। इसमें वह उपनिवेशक देश भी हो सकता था जिससे राजनीतिक आजादी हासिल की गई।

The idea of a New Inter national Economic Order (NIEO) originated with this realisation. The United **Nations Conference on Trade and Development** (UNCTAD) brought out a report in 1972 entitled **Towards a New Trade Policy for Development.** The report proposed a reform of the global trading system so as to:

इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन (य्नाइटेड नेशंस कॉनफ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट- अंकटाड) में 'टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार-प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुधारों से -

- (i) give the LDCs control over their natural resources exploited by the developed Western countries,
- (ii) obtain access to Western markets so that the LDCs could sell their products and, therefore, make trade more beneficial for the poorer countries,
- (iii) reduce the cost of technology from the Western countries, and
- (iv) provide the LDCs with a greater role in international economic institutions.

- (क) अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं;
- (ख) अल्प विकसित देशों की पहुँच पश्चिमी देशों के बाज़ार तक होगी; वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह ग़रीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा;
- (ग) पश्चिमी देशों से मंगायी जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी और (घ) अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़गी।

Gradually, the nature of nonalignment changed to give greater importance to economic issues. In 1961, at the first summit in Belgrade, economic issues had not been very important. By the mid-1970s, they had become the most important issues. As a result, NAM became an economic pressure group. By the late 1980s, however, the **NIEO** initiative had faded, mainly because of the stiff opposition from the developed countries who acted as a united group while the nonaligned countries struggled to maintain their unity in the face of this opposition.

गुटनिरपेक्षता की प्रकृति धोरे-धोरे बदली और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन (1961) में आर्थिक मुद्दे ज्यादा महत्त्वपूर्ण नहीं थे। सन् 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे। इसके परिणामस्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव-समूह बन गया। सन् 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाये-चलाये रखने के प्रयास मंद पड गए। इसका मुख्य कारण था विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे जबकि गुटनिरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी-तोड मेहनत करनी पड रही थी।

INDIA AND THE COLD WAR

As a leader of NAM, India's response to the ongoing Cold War was two-fold: At one level, it took particular care in staying away from the two alliances. Second, it raised its voice against the newly decolonised countries becoming part of these alliances.

भारत और शीतयुद्ध

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीतयुद्ध के दौर में भारत ने दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा। दूसरे, भारत ने उपनिवेशों के चुंगल से मुक्त हुए नव-स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया।

India's policy was neither negative nor passive. As Nehru reminded the world, nonalignment was not a policy of 'fleeing away'. On the contrary, India was in favour of actively intervening in world affairs to soften Cold War rivalries. India tried to reduce the differences between the alliances and thereby prevent differences from escalating into a fullscale war. Indian diplomats and leaders were often used to communicate and mediate between Cold War rivals such as in the Korean War in the early 1950s.

भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता की। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई 'पलायन' की नीति नहीं है। इसके विपरीत, भारत शीतयुद्धकालीन प्रतिद्वंदिता की जकड ढोलीकरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सिक्रय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। भारत के राजनियकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीतयुद्ध के दौर के प्रतिद्वंद्वियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता करने के लिए हुआ; मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान।

some suggest, a noble international cause which had little to do with India's real interests. A nonaligned posture also served India's interests very directly, in at least two ways:

Non-alignment was not, as कुछ लोगों ने माना कि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। यह बात ठीक नहीं है। गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हितसाधन किया -

- First, non-alignment allowed India to take international decisions and stances that served its interests rather than the interests of the super powers and their allies.
- Second, India was often able to balance one superpower against the other. If India felt ignored or unduly pressurised by one superpower, it could tilt towards the other. Neither alliance system could take India for granted or bully it.

India's policy of nonalignment was criticised on a number of counts. Here we

- •पहली बात तो यह कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत एसे अंतर्राष्ट्रीय फ़ैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित सधता होता हो न कि महाशक्तियों और उनके खेमे के देशों का।
- •दूसरे, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशिक्त उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशिक्त के करीब आने की कोशिश करे। अगर भारत को महसूस हो कि महाशिक्तयों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशिक्त की तरफ अपना रुख कर सकता था। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेप् कक्र हो सकता था और न ही धौंस जमा सकता था।

भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना की गई। हम यहां एसी दो आलोचनाओं की चर्चा करेंगे —

- First, India's non-alignment was said to be 'unprincipled'. In the name of pursuing its national interest, India, it was said, often refused to take a firm stand on crucial international issues.
- Second, it is suggested that India was inconsistent and took contradictory postures. Having criticised others for joining alliances, India signed the Treaty of Friendship in August 1971 with the USSR for 20 years. This was regarded, particularly by outside observers, as virtually
- •आलोचकों का एक तर्क यह है कि भारत की गुटनिरपेक्षता 'सिद्धांतिवहीन' है। कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा।
- •आलोचकों का दूसरा तर्क है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही। महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं सन् 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना माना।

Non-alignment as a strategy evolved in the Cold War context. As we will see in Chapter 2, with the disintegration of the USSR and the end of the Cold War in 1991, nonalignment, both as an international movement and as the core of India's foreign policy, lost some of its earlier relevance and effectiveness. However, nonalignment contained some core values and enduring ideas. It was based on a recognition that decolonised states share a historical affiliation and can become a powerful force if they come together. It meant that the poor and often very small countries of the world need not become followers of any of the big powers, that they could pursue an independent foreign policy. It was also based on a resolve to democratise the international system by thinking about an alternative world order to redress existing inequities. These core

गुटिनरपेक्षता की नीति शीतयुद्ध के संदर्भ में पनपी थी। दूसरे अध्याय में हम पढ़ंगे कि सन् 1990 के दशक के श्रुरुआती वषों में शीतयुद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता तथा प्रभावकारिता में थोड़ी कमी आयी। बहरहाल, गुटनिरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल हैं। गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आज़ाद हुए देशों के बीच एतिहासिक जुड़ाव हैं और यदि ये देश साथ आ जायें तो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। गुटनिरपेक्षता का आशय है। कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं। यह आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व-व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्रधर्मी बनाने के संकल्प पर भी टिका है। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्त्व के हैं और शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक हैं।

गुटनिरपेक्षता की नीति शीतयुद्ध के संदर्भ में पनपी थी। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि सन् 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में शीतयुद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता तथा प्रभावकारिता में थोड़ी कमी आयी। बहरहाल, गुटनिरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल हैं। गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आज़ाद हुए देशों के बीच एतिहासिक जुड़ाव हैं और यदि ये देश साथ आ जायें तो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। गुटनिरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं। यह आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व-व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्रधर्मी बनाने के संकल्प पर भी टिका है। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्त्व के हैं और शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक हैं।

LIMITED TEST BAN TREATY (LTBT)

Banned nuclear weapon tests in the atmosphere, in outer space and under water. Signed by the US, UK and USSR in Moscow on 5 August 1963. Entered into force on 10 October 1963.

सीमित परमाणु परीक्षण संधि (एलटीबीटी)

वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हिथयारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली इस संधि पर अमरीका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ ने मास्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए। यह संधि 10 अक्तूबर 1963 से प्रभावी हो गई।

NUCLEAR NON-PROLIFERATION TREATY (NPT)

Allows only the nuclear weapon states to have nuclear weapons and stops others from aquiring them. For the purposes of the NPT, a nuclear weapon state is one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to 1 January 1967. So there are five nuclear weapon states: US, **USSR** (later Russia), Britain, France and China. Signed in Washington, London, and Moscow on 1 July 1968. **Entered into force on 5 March**

परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी)

यह संधि केवल परमाणु शक्ति-संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है और बाकी देशों को एसे हथियार हासिल करने से रोकती है। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाण्-शक्ति से संपन्न देश माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोट किया हो। इस परिभाषा के अंतर्गत पाँच देशों - अमरीका, सोवियत संघ (बाद में रूस), ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को परमाणु-शक्ति से संपन्न माना गया। इस संधि पर एक जुलाई 1968 को वॉशिंग्टन, लंदन और मास्को में हस्ताक्षर हुए और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई। इस संधि को 1995 में अनियतकाल के लिए बढ़ा दिया गया।

STRATEGIC ARMS LIMITATION TALKS I (SALT-I)

The first round of the Strategic Arms Limitation Talks began in November 1969. The Soviet leader Leonid Brezhnev and the US President Richard Nixon signed the following in Moscow on 26 May 1972 –

- a) Treaty on the limitation of Anti-Ballistic Missile Systems (ABM Treaty); and
- b) Interim Agreement on the limitation of strategic offensive arms.

Entered into force on 3 October 1972.

सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता-। (स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स -साल्ट-।)

सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का पहला चरण सन् 1969 के नवम्बर में आरंभ हुआ। सोवियत संघ के नेता लियोनेड ब्रेझनेव और अमरीका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मास्को में 26 मई 1972 को निम्नलिखित समझौते पर दस्तख़त किए — (क) परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि (एबीएम ट्रोटी)।

(ख) सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन के बारे में अंतरिम समझौता।

ये 3 अक्तूबर 1972 से प्रभावी हुए।

STRATEGIC ARMS LIMITATION TALKS II (SALT-II)

The second round started in November 1972. The US President Jimmy Carter and the Soviet leader Leonid Brezhnev signed the Treaty on the limitation of strategic offensive arms in Vienna on 18 June 1979.

सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता-II (स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स-साल्ट-II)

वार्ता का दूसरा चरण सन् 1972 के नवम्बर महीने में शुरू हुआ। अमरीकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनेड ब्रेझनेव ने वियना में 18 जून 1979 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए।

STRATEGIC ARMS
REDUCTION TREATY I
(START-I)

Treaty signed by the USSR President Mikhail Gorbachev and the US President George Bush (Senior) on the reduction and limitation of strategic offensive arms in Moscow on 31 July 1991

सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि-। (स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन संधि-स्टार्ट-।)

अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश (सीनियर) और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने 31 जुलाई 1991 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन और उनकी संख्या में कमी लाने से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए।

STRATEGIC ARMS REDUCTION TREATY II (START-II)

Treaty signed by the Russian President Boris Yeltsin and the US President George Bush (Senior) on the reduction and limitation of strategic offensive arms in Moscow on 3 January 1993.

सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि-॥ (स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन संधि-स्टार्ट-॥)

सामरिक रूप से घातक हिथयारों को सीमित करने और उनकी संख्या में कमी करने से संबंधित इस संधि पर रूसी राष्ट्रपति बोरिस यल्तिसन और अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश (सीनियर) ने मास्को में 3 जनवरी 1993 को हस्ताक्षर किए।

- ➤ The Cold War produced an arms race as well as arms control. What were the reasons for both these developments?
- ▶शीतयुद्ध से हथियारों की होड और हथियारों पर नियंत्रण ये दोनों ही प्रक्रियाएँ पैदा हुईं। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे?

- >Why did the superpowers have military alliances with smaller countries? Give three reasons.
- महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थीं? तीन कारण बताइए?

- Sometimes it is said that the Cold War was a simple struggle for power and that ideology had nothing to do with it. Do you agree with this? Give one example to support your position.
- ▶कभी-कभी कहा जाता है कि शीतयुद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण दें।

- ➤ What was India's foreign policy towards the US and USSR during the Cold War era? Do you think that this policy helped India's interests?
- >शीतयुद्ध के दौरान भारत की अमरीका और सोवियत संघ के प्रित विदेश नीति क्या थी? क्या आप मानते हैं कि इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया?

- ➤ NAM was considered a 'third option' by Third World countries. How did this option benefit their growth during the peak of the Cold War?
- >गुट-निरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीतयुद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुँचाई?

- ➤ What do you think about the statement that NAM has become irrelevant today. Give reasons to support your opinion.
- ┢'गुट-निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है'। आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करें।